लघु उद्योगों के लिये सुविधाओं को बढ़ाया जाना

3134. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े और मध्यम उद्योगों के समान ही लघु उद्योगों को कच्चे माल, बैंक ऋणों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक नीति की घोषणा किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) प्रस्तावित नई लघु उद्योग नीति को कब तक लाग किया जाएगा और

(घ) इस नीति से कितने और किस प्रकार के लघु उद्योगों को लाभ पहुंचेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम : (क) 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों में सरकार ने लघु उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाओं की परिकल्पना की है । सरकार ने कच्चे माल के संबंध में उदारीकृत नीतियों की घोषणा पहले ही कर दी है जिनके कारण लघु एकक अपेक्षित मात्रा में कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं । जिस कच्चे माल की कमी है उसे आयात तथा निर्यात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है और इसका कम सीमा शुल्क पर निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है । ऋण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु क्षेत्र की पर्याप्त एवं समय पर ऋण सुनिश्चित कराने हेतु अपने तारीख 17 अप्रैल, 1993 और 3 जुलाई 1993 के परिपत्रों के द्वारा उपायों के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है जिन की मुख्य बातों में निम्नलिखित शामिल है :–

(1) इसके बाद ग्रामीण, अति लघु उद्योगों तथा अन्य लघु औद्योगिक एककों जिनकी बैंकिंग प्रणाली से निधि आधारित कार्यशील पूंजी ऋण की सीमा एक करोड रु० तक है को नए तथा मौजूदा एककों के लिए अपने वार्षिक अनुमानित उत्पादन के न्यूनतम 20 प्रतिशत आधार पर संगणित कार्याशील पूंजी उपलब्ध करायी जाए ।

(2) ऋण प्राप्त करने वाले लघु उद्योगों से प्राप्त आवेदनों के निपटान हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-सीमा को सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए ।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के स्वीकृत बुनियादी विकास की एक योजना भी तैयार की गई है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग नीति का कोई नया विस्तृत [illegible] आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Attracting German Investors to India

3135. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Germany which used to be the second largest investor in India, had gone down to the tenth position after 1990; and

(b) how far the recent visit by the Prime Minister and his team to Germany is likely to improve the position by way of attracting German investors to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Amount of foreign direct investment by German companies approved has increased from Rs. 41.8 crores in 1991 to Rs. 86.3 crores in 1992 and Rs. 175.9 crores in 1993. However, in the list of coun-